चिकित्सीय
आपातकाल/एम्बुलेंस सेवा के लिए
कृपया 112 पर डायल करें।

अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 | संख्या 236 | श्री विजय पुरम, गुरूवार , 03 सितम्बर 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए

माननीय प्रधानमंत्री ने पानी पर आयोजित राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की

माननीय प्रधानमंत्री ने ठोस और समयबद्ध नतीजों पर अमल करने के लिए लगातार समीक्षा और फॉलो–अप की प्रक्रिया अपनाने पर ज़ोर दिया

माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एवं उपाध्यक्ष, द्वीप विकास एजेंसी एडमिरल डी.के. जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.) ने आज नई दिल्ली में जल संरक्षण एवं सुरक्षा पर आयोजित विभागीय शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन में भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया तथा सतत जल प्रबंधन एवं जल सुरक्षा के संबंध में अपने दृष्टिकोण को साझा किया।

नई दिल्ली, 2 सितम्बर। (प.सू.का.)

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पानी पर आधारित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। यह शिखर सम्मेलन टीम इंडिया की भावना को मजबूत करने, सहकारी संघवाद को गहरा करने और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर सहयोग के जरिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक ज़िम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की सोच के अनुरुप विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला सम्मेलन है। इसमें भारत की जल सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित चर्चा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी एक साथ एक मंच पर थे।

प्रधानमंत्री ने दो दिनों तक चली गहन चर्चा की सराहना की और इस बात पर ज़ोर दिया कि शिखर सम्मेलन से निकले कार्यान्वयन योग्य और समय–सीमा वाले कार्य बिंदुओं की समीक्षा और सीखने की निरंतर प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि यह शिखर सम्मेलन केवल एक बार की गतिविधि बनकर नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने इसकी समीक्षा व फॉलो अप की निरंतर प्रक्रिया का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने शहरीकरण से जुड़ी चुनौतियों, जैसे आबादी का बढ़ना और भविष्य में पानी की जरूरतों के बारे में शहरी स्थानीय निकायों को जागरूक करने पर ज़ोर दिया और उनके लिए भी ऐसे ही चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। उन्होंने पानी बचाने वाली तकनीकों को ज़्यादा अपनाने की बात कही। उन्होंने भारतीय निर्माताओं और संबंधित लोगों को असरदार समाधान विकसित करने और उन्हें बड़े पैमाने पर लागू करने में मदद करने के लिए खास प्रदर्शनियों और कार्यशालाएं, जिनमें दुनिया भर के बेहतरीन तरीकों की जानकारी भी शामिल हो, आयोजित करने का सुझाव भी दिया।

जन भागीदारी पर ज़ोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने लोगों में ज़्यादा जागरूकता लाने के लिए "जल उत्सव" को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने गाद निकालने के काम को एक नियमित कार्यक्रम बनाने और इसके लिए साफ नियम और मानक संचालन प्रक्रिया बनाने को कहा। बांध की सुरक्षा के मामले में, उन्होंने हर मॉनसून से पहले पूरी तैयारी रखने, तय सावधानियों का पालन करने और स्कूली छात्रों में जागरूकता पैदा करने पर ज़ोर दिया, जिसमें शिक्षा के पाठ्यक्रम में इसे सही ढंग से शामिल करना भी शामिल है।

प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में भी जल प्रबंधन और शासन के बारे में जानकारी और क्षमता बढ़ाने पर ज़ोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि जन–प्रतिनिधियों, अधिकारियों और किसानों के बीच व्यवस्थित अंतर–राज्यीय अध्ययन–दौरे आयोजित किए जाएं, ताकि व्यावहारिक सीख मिल सके और सफल उपायों को दूसरी जगहों पर भी अपनाया जा सके।

प्रधानमंत्री ने मजबूत जल डेटा गवर्नेंस की जरूरत पर ज़ोर दिया, जिसमें जल–क्षेत्र से जुड़े डेटा को एक साथ लाया जाए, उसे व्यवस्थित रूप से प्रबंधित किया जाए और उसका विश्लेषण तथा प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। उन्होंने एक समान प्रारूप के माध्यम से डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए एआई के उपयोग की भी सिफारिश की। उन्होंने कृषि और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपचारित पानी के उचित उपयोग के जरिए पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहले से तैयारी और एकीकृत योजना बनाने पर भी ज़ोर दिया।

गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने अनुभव का ज़िक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि सही योजना, पक्के इरादे, जरूरी संसाधन तथा काबिल अधिकारियों को लगाकर पानी की कमी की समस्या को एक अवसर में बदला जा सकता है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल ने सम्मेलन के चार मुख्य नतीजों पर ज़ोर दिया: पानी से जुड़ी ढ़ांचागत परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना, जल संरक्षण को लोगों के एक लगातार चलने वाले आंदोलन के तौर पर मजबूत करना, पीने योग्य पानी के स्रोतों की लंबे समय तक उपलब्धता सुनिश्चित करना और गांवों में पीने के पानी की योजनाओं के असरदार संचालन और रखरखाव को संस्थागत रूप देना।

डॉलीगंज में 20 एमडब्ल्यूएच से जुड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली हेतु निविदाएं आमंत्रित

सांकेतिक तस्वीर

नई दिल्ली, 2 सितंबर।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के विद्युत विभाग ने श्री विजय पुरम के डॉलीगंज में 20 एमडब्ल्यूएच ग्रिड से जुड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) की स्थापना के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की हैं। यह निविदा भारत के राष्ट्रपति की ओर से एफ. संख्या ईएल/पीएल–2/3/2026/2544 के तहत जारी की गई है।

प्रस्तावित बीईएसएस परियोजना का विकास नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (आरईएससीओ) मॉडल के अंतर्गत बिल्ड–ओन–ऑपरेट (बीओओ) आधार पर किया जाएगा। अनुबंध की अवधि 12 वर्ष होगी, जिसमें संचालन एवं अनुरक्षण (ओ व एम) की समग्र ज़िम्मेदारी भी शामिल रहेगी। इस परियोजना का उद्देश्य दक्षिण अण्डमान क्षेत्र में विद्युत ग्रिड की स्थिरता बढ़ाना तथा अधिकतम विद्युत मांग (पीक डिमांड) के प्रभावी प्रबंधन को समर्थन देना है।

परियोजना की सांकेतिक पूंजीगत लागत 60 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है, जिसे वित्तीय पात्रता तय करने के मानक के रूप में माना जाएगा। निविदाकारों को 1.20 करोड़ रुपये की धरोहर राशि (ईएमडी/बिड सिक्योरिटी) जमा करनी होगी। हालांकि, निर्धारित पंजीकरण मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों (एमएसएमई) को बिड सिक्योरिटी से छूट प्रदान की जाएगी।

परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (पीबीजी), निविदा प्रस्तुत करने की समय–सारिणी, प्री–बिड बैठक तथा तकनीकी निविदा खोलने की तिथि संबंधी विस्तृत जानकारी केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) पर उपलब्ध टेंडर सूचना अनुसूची (टीआईएस) में प्रकाशित की जाएगी।

यह परियोजना दक्षिण अण्डमान में विद्युत नेटवर्क को सुदृढ़ करने तथा पीक डिमांड के प्रबंधन के लिए अतिरिक्त लचीलापन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। (स्रोत: https://solarquarter.com)

आवास एवं शहरी कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने द्वीपों में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

श्री विजय पुरम, 2 सितंबर।

आवास एवं शहरी कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति (2025–2026) के अध्यक्ष श्री मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के नेतृत्व में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के तीन दिवसीय दौरे पर आई समिति ने आज अण्डमान तथा निकोबार संघ राज्य क्षेत्र, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग, श्री विजय पुरम नगरपालिका परिषद, हुडको, एनबीसीसी, सीपीडब्ल्यूडी, भारतीय स्टेट बैंक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक चर्चा की। यह चर्चा स्वराज द्वीप स्थित ताज एक्सोटिका के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। चर्चा के दौरान श्री विजय पुरम में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों, जैसे अमृत एवं अमृत 2.0, स्वच्छ भारत मिशन–शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0, प्रधानमंत्री स्वनिधि, अर्बन चैलेंज फंड, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम), प्रधानमंत्री ई–बस सेवा तथा एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) और विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) आदि के संचालन एवं प्रदर्शन की समीक्षा तथा प्रगति पर चर्चा की गई। इसके अलावा, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सीपीडब्ल्यूडी, एनबीसीसी एवं हुडको के कामकाज़ की समीक्षा तथा श्री विजय पुरम नगरपालिका परिषद की मानव संसाधन क्षमता, राजस्व जुटाने एवं बजट प्रबंधन से संबंधित विषयों पर भी विचार–विमर्श किया गया।

जम्स ऑफ इंडिया चैलेंज 2026

पायलट सबमिशन विंडो की तिथि 30 सितम्बर तक बढ़ी

श्री विजय पुरम, 2 सितंबर।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की राष्ट्रीय पहल जम्स ऑफ इंडिया चैलेंज 2026, जिसे प्रसार भारती के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, ने नागरिकों, विशेषकर युवाओं एवं डिजिटल कंटेंट निर्माताओं को अपने–अपने ज़िलों की संस्कृति, विरासत, पर्यटन क्षमता, परंपराओं, खान–पान, कला एवं स्थानीय स्तर की प्रेरणादायक कहानियों को राष्ट्रीय डिजिटल मंच पर प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया है।

इस पहल को पायलट चरण में छह राज्यों व संघ राज्य

शेष पृष्ठ 4 पर

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भाषा प्रयोगशाला पर जागरूकता कार्यक्रम

डिगलीपुर, 2 सितंबर।

समग्र शिक्षा के तहत ब्लॉक परियोजना कार्यालय (बीपीओ), डिगलीपुर, उत्तर अण्डमान द्वारा आज सीआरसी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, डिगलीपुर में 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए भाषा प्रयोगशाला' विषय पर जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पूर्व–प्राथमिक शिक्षकों, अभिभावकों/परिवार के सदस्यों, एसएमसी/एसएमडीसी सदस्यों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, देखभालकर्ताओं/सहायकों तथा अन्य हितधारकों के लिए आयोजित किया गया, ताकि उन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समग्र विकास के लिए भाषा प्रयोगशाला के प्रभावी उपयोग के बारे में संवेदनशील एवं जागरूक बनाया जा सके।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम में भाषा प्रयोगशाला के विभिन्न उपयोगों एवं लाभों पर जानकारीपूर्ण सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों को भाषा प्रयोगशाला के प्रभावी उपयोग तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षिक, डिजिटल, मनोरंजक, नेतृत्व, भाषाई एवं समग्र विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में इसकी संभावनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई।

मुर्गीपालन क्षेत्र में रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण में टीकाकरण के महत्व पर प्रशिक्षण संचालित

श्री विजय पुरम, 2 सितंबर।

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग, दक्षिण अण्डमान द्वारा यूटी–एटीएमए के तहत 28 एवं 29 अगस्त, 2026 को वंडूर ग्राम पंचायत, दक्षिण अण्डमान में 'मुर्गीपालन क्षेत्र में रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण में टीकाकरण का महत्व' विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

आईसीएआर–सीआईएआरआई एवं कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), श्री विजय पुरम के विशेषज्ञों के साथ–साथ केंद्रीय हैचरी, डॉलीगंज एवं केंद्रीय पशुधन फार्म (सीएलएफ), डॉलीगंज के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों ने तकनीकी सत्र आयोजित किए तथा सहभागी किसानों के साथ संवाद किया। वंडूर ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान श्री अधीर दास ने भी कार्यक्रम में भाग लिया तथा किसानों को वैज्ञानिक मुर्गीपालन पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

प्रशिक्षण में समय पर टीकाकरण, मुर्गियों में होने वाले प्रमुख रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण, वैज्ञानिक स्वास्थ्य प्रबंधन, जैव–सुरक्षा, स्वच्छता तथा झुंड के सामान्य प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। किसानों को मुर्गीपालन में रोगों से होने वाले नुक़सान को कम करने तथा उत्पादकता बढ़ाने में निवारक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व के बारे में भी जागरूक किया गया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम की एक विशेष विशेषता मुर्गियों में होने वाले प्रमुख संक्रामक रोगों पर दृश्य प्रस्तुति थी। कार्यक्रम में किसान–विशेषज्ञ संवाद का अवसर भी प्रदान किया गया, जिसके दौरान मुर्गियों के स्वास्थ्य एवं रोगों की रोकथाम से संबंधित व्यावहारिक समस्याओं पर चर्चा की गई। प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र भी वितरित किए गए।

राजीव नगर में लगा बांझपन निवारण शिविर

श्री विजय पुरम, 2 सितंबर।

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा 29 अगस्त, 2026 को कैम्पबेल बे के राजीव नगर में बांझपन निवारण शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर द्वीपसमूह में गोवंश के प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार के लिए आयोजित किए जा रहे बांझपन निवारण शिविरों की निरंतर श्रृंखला के तहत आयोजित किया गया।

शिविर के दौरान कुल 16 पशुओं को कृमिनाशक दवा दी गई तथा पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए 16 पशुओं को खनिज मिश्रण अनुपूरक प्रदान किया गया। तीन पशुओं को टोनोफोस्फान इंजेक्शन दिया गया। अनीस्ट्रस की स्थिति से ग्रस्त पाए गए तीन मवेशियों को एस्ट्रोसिड बोलस तथा अनीस्ट्रस एवं पोषण संबंधी कमी से ग्रस्त तीन मवेशियों को रुमेंटास बोलस दिया गया। शिविर में उपस्थित पशुपालकों को बेहतर प्रजनन स्वास्थ्य एवं उत्पादकता के लिए मवेशियों के वैज्ञानिक पोषण प्रबंधन के संबंध में भी सलाह दी गई। इसमें संतुलित आहार देने, पर्याप्त हरा चारा, सांद्रित आहार एवं स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने पर ज़ोर दिया गया। बांझपन से संबंधित समस्याओं का समय पर उपचार तथा दुधारू पशुओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के महत्व पर भी विशेष बल दिया गया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह शिविर गोवंश में बांझपन की समस्याओं के समाधान तथा समय पर निदान, उपचार एवं पोषण संबंधी सहायता के माध्यम से डेयरी किसानों को सहयोग प्रदान करने के विभाग के निरंतर प्रयासों का हिस्सा था। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वीपसमूह में नियमित रूप से बांझपन निवारण शिविर आयोजित कर पशुधन उत्पादकता बढ़ाने तथा डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मौसम संबंधी पूर्वानुमान

श्री विजय पुरम, 2 सितंबर।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में 3 से 8 सितंबर, 2026 तक एक या दो स्थानों पर गरज–चमक के साथ आंधी–तूफान तथा तेज हवाएं, जिनकी गति 30–40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है।

आपदा प्रबंधन निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार 3 सितंबर, 2026 को 17.30 बजे तक 16.0 से 17.0 सेकंड अवधि तथा 2.0 से 2.2 मीटर ऊंचाई वाली ऊंची समुद्री लहरों (स्वेल वेव्स) का पूर्वानुमान है। सलाह दी गई है कि लहरों के उफान मारने की संभावना को देखते हुए नावों का संचालन अत्यंत सतर्कता के साथ किया जाए तथा मनोरंजक गतिविधियां भी उचित सावधानी के साथ की जाएं। अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में एक या दो स्थानों पर गरज–चमक के साथ 40–50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली तेज हवाएं चलने की संभावना है।

पायलट सबमिशन विंडो की तिथि 30 सितम्बर

पृष्ठ 1 का शेष

क्षेत्रों, अर्थात अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, गोवा तथा लद्दाख में लागू किया जा रहा है। पायलट सबमिशन विंडो, जो पहले 1 अगस्त से 31 अगस्त, 2026 तक निर्धारित थी, अब 30 सितंबर, 2026 तक बढ़ा दी गई है। प्रतिभागी वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत **MyWAVES** मंच के माध्यम से अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह चैलेंज अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लोगों, विशेषकर युवा रचनाकारों के लिए देशभर के दर्शकों के समक्ष द्वीपों की अनूठी पहचान, प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, खान–पान, पर्यटन आकर्षणों एवं प्रेरणादायक कहानियों को प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। व्यापक जागरूकता पैदा करने एवं लोगों को भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वेव्स ओटीटी की मौजूदा सोशल मीडिया टीम ने स्थिर क्रिएटिव, कैरोसेल, रील्स एवं प्रचार वीडियो सहित विभिन्न प्रचार सामग्री भी तैयार की है।

वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के **MyWAVES** अनुभाग में पंजीकरण एवं नामांकन पहले से ही खुले हैं तथा प्रतिभागी 30 सितंबर, 2026 तक अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं। इसलिए, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय (आईपीएंडटी) ने द्वीपसमूह के इच्छुक रचनाकारों, युवाओं, विद्यार्थियों, पर्यटन प्रेमियों एवं नागरिकों से इस अवसर का लाभ उठाने तथा जम्स ऑफ इंडिया चैलेंज 2026 में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है।

अधिक जानकारी एवं पंजीकरण के लिए प्रतिभागी वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के **MyWAVES** अनुभाग पर जा सकते हैं।

संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा एवं आशुलिपिक ग्रेड 'सी' और 'डी' परीक्षा 8 से 12 सितंबर तक

श्री विजय पुरम, 2 सितंबर।

उप सचिव (भर्ती एवं परीक्षा) से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा, 2026 तथा आशुलिपिक ग्रेड 'सी' एवं 'डी' परीक्षा, 2026 का आयोजन 8 सितंबर, 2026 से 12 सितंबर, 2026 तक किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के ई–प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट **https://ssc.gov.in /https://sscer.org)** पर निर्धारित परीक्षा तिथि से 3–4 दिन पहले उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

इग्नू ने जुलाई 2026 सत्र के लिए नए प्रवेश और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ाई

श्री विजय पुरम, 2 सितंबर।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई, 2026 सत्र के लिए सर्टिफिकेट कार्यक्रमों को छोड़कर सभी कार्यक्रमों में नए प्रवेश और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर, 2026 कर दी है।

इग्नू स्नातकोत्तर, स्नातक, स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा डिप्लोमा स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करता है। इग्नू द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रम यूजीसी द्वारा मान्य हैं तथा इनका उपयोग पदोन्नति और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षाओं के लिए किया जा सकता है। नियमित माध्यम से स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री कर रहे विद्यार्थी दोहरी डिग्री योजना के तहत इग्नू में भी प्रवेश ले सकते हैं। इग्नू में नए प्रवेश और पुनः पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। विद्यार्थी इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट **www.ignou.ac.in** पर "स्टूडेंट सर्विस–एडमिशन सेक्शन" पर जाकर नए प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं तथा विद्यार्थियों के लिए इग्नू समर्थ पोर्टल के माध्यम से पुनः पंजीकरण पूरा कर सकते हैं।

इग्नू द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षार्थियों के लिए व्यापक स्तर पर पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनमें कृषि, स्वास्थ्य विज्ञान, विदेशी भाषाएं, सामाजिक विज्ञान, प्रबंधन, जनसंचार एवं मीडिया, यात्रा एवं पर्यटन, अनुवाद अध्ययन, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान आदि शामिल हैं।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यदि किसी शिक्षार्थी को ऑनलाइन प्रवेश या पुनः पंजीकरण फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होती है, तो वह इग्नू क्षेत्रीय केंद्र, पोर्ट ब्लेयर, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के सामने, वीआईपी रोड, जंगलीघाट डाकघर, श्री विजय पुरम से संपर्क कर सकता है। दूरभाष नंबर 03192–242888 या 03192–230111 तथा ई–मेल **rcportblair@ignou.ac.in** है।

धान की उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने पर फील्ड डे कार्यक्रम

श्री विजय पुरम, 2 सितंबर।

आईसीएआर–केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर–सीआईएआरआई), श्री विजय पुरम द्वारा आईसीएआर–कृषि विज्ञान केंद्र, दक्षिण अण्डमान के सहयोग से 2 सितंबर, 2026 को छोलदारी स्थित ब्लूम्सडेल अनुसंधान फार्म में "उच्च उपज वाली धान की किस्मों के प्रदर्शन के माध्यम से धान की उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाना" विषय पर फील्ड डे कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन आईसीएआर–सीआईएआरआई, श्री विजय पुरम के निदेशक डॉ. जय सुंदर के समग्र मार्गदर्शन में किया गया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में फार्म प्रबंधक श्री के. श्याम सुंदर राव ने उत्तर व मध्य अण्डमान से आए किसानों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने द्वीपों के किसानों एवं अन्य हितधारकों के लाभ के लिए ब्लूम्सडेल अनुसंधान फार्म में किए जा रहे अनुसंधान एवं फार्म प्रबंधन संबंधी गतिविधियों का अवलोकन प्रस्तुत किया।

एफसीआईपी अनुभाग के प्रभारी प्रमुख एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉ. पी. के. सिंह ने खेत में आईसीएआर–सीआईएआरआई द्वारा विकसित विभिन्न उच्च उपज वाली धान की किस्मों के प्रदर्शन का प्रस्तुतीकरण किया तथा संस्थान द्वारा विकसित उन्नत किस्मों एवं उन्नत उत्पादन तकनीकों का प्रदर्शन किया। उन्होंने किसानों के साथ संवाद भी किया तथा उनके सामने आने वाली विभिन्न कृषि संबंधी समस्याओं एवं चुनौतियों पर चर्चा की।

आईसीएआर–कृषि विज्ञान केंद्र, दक्षिण अण्डमान के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. वाई. रामकृष्ण ने प्राकृतिक खेती आधारित धान के खेत का प्रदर्शन किया तथा टिकाऊ, पर्यावरण–अनुकूल एवं जलवायु–सहिष्णु कृषि को बढ़ावा देने में प्राकृतिक खेती पद्धतियों के महत्व पर प्रकाश डाला।

वैज्ञानिक डॉ. प्रभु पी. ने सहभागी किसानों के साथ संवाद किया तथा उनसे आईसीएआर–सीआईएआरआई द्वारा विकसित उन्नत धान की किस्मों एवं उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने की अपील की। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उपयुक्त उन्नत तकनीकों को अपनाने से फसल की उत्पादकता एवं उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है, किसानों की आजीविका में सुधार किया जा सकता है तथा द्वीपों में टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दिया जा सकता है।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि कार्यक्रम में उत्तर व मध्य अण्डमान के कुल 43 किसानों ने भाग लिया, जिनमें 32 महिलाएं एवं 11 पुरुष शामिल थे। किसानों ने तकनीकी विचार–विमर्श, किसान–वैज्ञानिक संवाद तथा खेत में किए गए प्रदर्शनों से लाभ प्राप्त किया। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के कृषि निदेशालय के अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का समापन तकनीकी सहायक श्री बिकाश चंद्र मंडल के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

टीजीसीई में दो वर्षीय बी.एड. डिग्री कार्यक्रम की रिक्त सीटों के लिए काउंसलिंग 7 सितंबर को

श्री विजय पुरम, 2 सितंबर।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस उच्च शिक्षा संस्थान (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), श्री विजय पुरम के घटक महाविद्यालय टीजीसीई में दो वर्षीय बी.एड. डिग्री कार्यक्रम की कुछ सीटें रिक्त हो गई हैं। इन रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए 7 सितंबर, 2026 को सुबह 9.30 बजे टीजीसीई के सभागार में काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक सभी पात्र अभ्यर्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे उपर्युक्त तिथि एवं समय पर काउंसलिंग में उपस्थित हों। चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश के दिन सभी मूल प्रमाण–पत्रों के साथ सभी मूल प्रमाण–पत्रों की एक–एक छायाप्रति का सेट तथा निर्धारित शुल्क की राशि जमा करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उन्हें प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जाएगा। मौजूदा नियमों के अनुसार, यदि किसी विषय में श्रेणी–1 या किसी अन्य श्रेणी में सीटें रिक्त रहती हैं, तो उन सीटों को उसी विषय में सामान्य श्रेणी–5 से, महाविद्यालय द्वारा पहले से प्रकाशित अंतिम मेरिट सूची के आधार पर आवंटित किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि उस श्रेणी में कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है, तो सीटें संयुक्त अंतिम मेरिट सूची में शामिल सामान्य श्रेणी–5 के अन्य पात्र अभ्यर्थियों को आवंटित की जाएंगी।

दो वर्षीय बी.एड. डिग्री कार्यक्रम की रिक्त सीटों का विवरण

क्र.सं.	विषय	श्रेणी	रिक्ट सीटों की संख्या
1.	कंप्यूटर	1	1 सीट
2.	वाणिज्य	1	1 सीट
3.	गृह विज्ञान	5	1 सीट
4.	गणित	1	1 सीट
5.	रसायन विज्ञान	1	1 सीट
6.	भौतिकी विज्ञान	1	2 सीटें
		4	1 सीट
7.	वनस्पति विज्ञान/पादम विज्ञान	1	1 सीट
		3–ए	1 सीट
8.	प्राणी विज्ञान	1	1 सीट
9.	इतिहास	1	1 सीट
10	अर्थशास्त्र	1	1 सीट
11	हिंदी	1	1 सीट
कुल			17 सीटें

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार जो अभ्यर्थी उपर्युक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर काउंसलिंग सत्र में उपस्थित नहीं होंगे, उन्हें पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जाएगा तथा मेरिट सूची में उनके बाद आने वाले अगले पात्र अभ्यर्थी को प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

ईपीएफ योजना 2026 में माफी प्रावधानों के माध्यम से भविष्य निधि ट्रस्टों की छूट स्थिति का पूर्वव्यापी नियमितीकरण

नई दिल्ली, 02 सितम्बर।

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना 2026 में अवस्था परिवर्तनकालिक उपाय के रूप में माफी के प्रावधान पेश किए गए हैं, जिन्हें 29.06.2026 को अधिसूचित किया गया था। ये प्रावधान उन भविष्य निधि (पीएफ) ट्रस्टों की छूट स्थिति को नियमित करने का एक बार का अवसर प्रदान करते हैं, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत मान्यता प्राप्त है, लेकिन जिनके पास कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 की धारा 17 या सामाजिक सुरक्षा संहिता (सीओएसएस), 2020 की धारा 143 के तहत औपचारिक छूट आदेश नहीं है।

माफी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया, प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं आदि सहित परिचालन दिशानिर्देश 11.07.2026 को जारी विस्तृत परिपत्र में दिए गए थे। इस माफी योजना के प्रावधान अधिसूचना की तिथि से छह महीने की अवधि के लिए यानी 28.12.2026 तक वैध हैं। छूट प्राप्त स्थिति के पूर्वव्यापी नियमितीकरण के अलावा, पीएफ ट्रस्टों को मिलने वाले अन्य प्रमुख लाभों में न्यूनतम कर्मचारी संख्या, कोष का आकार और 3–वर्षीय अनुपालन नियम जैसी कुछ आवश्यकताओं से छूट शामिल है, जो कि सीओएसएस, 2020 के अंतर्गत हैं। पूर्वव्यापी आधार पर नियमितीकरण के बाद, कोई प्रतिष्ठान छूट प्राप्त या गैर–छूट प्राप्त प्रतिष्ठान के रूप में अनुपालन करना चुन सकता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है कि संभावित आवेदकों को माफी योजना के प्रावधानों के बारे में पूरी जानकारी दी जाए और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से उन्हें पूरी प्रक्रिया में उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। इस अभियान के तहत विभिन्न हितधारकों के साथ संपर्क जारी है। ईपीएफओ ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) जैसे पेशेवर संगठनों से संपर्क किया है, जिनके सदस्य (सीए) कई प्रतिष्ठानों का वैधानिक या आयकर लेखा परीक्षा करते हैं, जिनमें से कई मामलों में ऐसे प्रतिष्ठानों ने पीएफ ट्रस्ट फंड बनाए हैं और वे उन पीएफ ट्रस्टों की पहचान करने में सक्षम हैं जो संभावित रूप से माफी योजना का लाभ उठा सकते हैं। आईसीएआई से अनुरोध किया गया है कि वह अपने सदस्यों के बीच माफी योजना के प्रावधानों का प्रसार करे ताकि पीएफ ट्रस्टों से योजना के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हो सके। इसके अलावा, ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों जैसे उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय और कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने हितधारकों के साथ सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित की हैं।

इसके अतिरिक्त, ईपीएफओ ने आयकर विभाग से आयकर अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त पीएफ ट्रस्टों का विवरण मांगा है और अनुरोध किया है कि आयकर अधिनियम के तहत मान्यता देने से पहले या ईपीएफओ से औपचारिक छूट आदेश प्राप्त न करने वाले पीएफ ट्रस्टों की मौजूदा मान्यता वापस लेने से पहले, ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 या सीओएसएस, 2020 के तहत प्रतिष्ठान की कवरेज और छूट की स्थिति की संबंधित जांच की जाए।

संस्थानों के पीएफ ट्रस्ट, ईपीएफओ के दिनांक 11.07.2026 के परिपत्र (ईपीएफओ की वेबसाइटः https://www.epfo.gov.in पर उपलब्ध है) में उल्लिखित विवरण के अनुसार माफी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना से बदली वित्तीय तस्वीर, 12 साल में 59 करोड़ से ज्यादा खाते खुले

नई दिल्ली, 02 सितम्बर।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) की शुरुआत देश के हर नागरिक को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से की थी। 12 साल की यात्रा में यह पहल दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में शामिल हो गई है। बैंक खाते खोलने से शुरू हुई जन धन योजना अब बचत, बीमा, पेंशन, ऋण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और डिजिटल भुगतान तक आम लोगों की पहुंच का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। 19 अगस्त 2026 तक देश में जन धन खातों की संख्या बढ़कर 59.09 करोड़ हो गई है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के पीछे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वित्तीय समावेशन का मूल विचार यह रहा है कि बैंक खाता किसी खास वर्ग के लिए उपलब्ध सुविधा नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए बुनियादी वित्तीय अवसर होना चाहिए। योजना ने उन करोड़ों लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का काम किया, जो लंबे समय तक इससे बाहर रहे थे। योजना के तहत केवल बैंक खाते ही नहीं खोले गए, बल्कि खाताधारकों को बचत, बीमा, पेंशन, ऋण और डिजिटल वित्तीय सेवाओं से जोड़ने का रास्ता भी तैयार हुआ। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों की औपचारिक वित्तीय व्यवस्था में भागीदारी बढ़ी है।

जन धन योजना के विस्तार का अंदाजा इसके आंकड़ों से लगाया जा सकता है। वर्ष 2015 में PMJDY खातों की संख्या 14.72 करोड़ थी, जो 19 अगस्त 2026 तक बढ़कर 59.09 करोड़ हो गई। यानी 12 साल में जन धन खातों की संख्या करीब चार गुना बढ़ी है। इनमें 45.95 करोड़ खाते ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में हैं, जबकि 13.14 करोड़ खाते शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में हैं। आंकड़े बताते हैं कि योजना के जरिए बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण और ऐसे इलाकों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया, जहां बड़ी आबादी पहले औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से दूर थी।

जन धन योजना की प्रमुख उपलब्धियों में महिलाओं की बढ़ती वित्तीय भागीदारी भी शामिल है। 19 अगस्त 2026 तक च्डश्रक्ल खातों के 32.92 करोड़ लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं के नाम पर बैंक खाते होने से उन्हें अपनी बचत और वित्तीय निर्णयों पर अधिक नियंत्रण का अवसर मिलता है। इससे आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के साथ परिवार और समाज में महिलाओं की वित्तीय भागीदारी मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

जन धन योजना के प्रभाव का एक बड़ा संकेत खातों में जमा राशि में हुई वृद्धि है। मार्च 2015 में PMJDY खातों में कुल जमा राशि 15,670 करोड़ रुपए थी, जो अगस्त 2026 में बढ़कर 3,16,514 करोड़ रुपए हो गई। इस तरह इस अवधि में जमा राशि में करीब 20 गुना वृद्धि हुई। यह औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था में लोगों की बढ़ती भागीदारी और बैंकिंग प्रणाली में बढ़ते भरोसे का संकेत है। साथ ही इससे निम्न आय वर्ग के परिवारों में बैंकिंग के जरिए बचत की प्रवृत्ति मजबूत होने का भी पता चलता है।

जन धन योजना का उद्देश्य सिर्फ बैंक खाता उपलब्ध कराना नहीं रहा है। PMJDY खातों के जरिए लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की सुविधा मिलती है। पात्र लाभार्थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और मुद्रा जैसी योजनाओं से भी जुड़ सकते हैं। निर्धारित शर्तों के अधीन पात्र खाताधारकों को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी उपलब्ध है। इससे जरूरत के समय औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से छोटी राशि हासिल करने का अवसर मिलता है और अनौपचारिक वित्तीय स्रोतों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

जन धन खाताधारकों को जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड ने उन्हें डिजिटल वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 19 अगस्त 2026 तक PMJDY खाताधारकों को 41.29 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके थे। अगस्त 2018 के बाद खोले गए नए जन धन खातों के लिए निर्धारित प्रावधानों के तहत बिना किसी प्रीमियम के 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर भी उपलब्ध है। इस तरह योजना ने बैंकिंग सुविधा के साथ खाताधारकों के लिए वित्तीय सुरक्षा का आधार भी तैयार किया है।

देश में वित्तीय समावेशन की व्यापक तस्वीर भी इस बदलाव को दर्शाती है। भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक 2018 में 53.9 था, जो 2026 में बढ़कर 67 हो गया। यह वृद्धि बचत, ऋण, बीमा और डिजिटल भुगतान जैसी वित्तीय सेवाओं तक लोगों की पहुंच में सुधार को दर्शाती है। जन धन योजना की शुरुआत के शुरुआती दौर में बड़े पैमाने पर खाते खोलने का अभियान चलाया गया था। जनवरी 2015 में एक सप्ताह के दौरान 1,80,96,130 बैंक खाते खोले गए थे। इस उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। योजना को औपचारिक बैंकिंग तक पहुंच बढ़ाने के प्रयासों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से भी मान्यता मिली है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना का व्यापक असर नागरिकों और औपचारिक वित्तीय व्यवस्था के बीच संबंध में बदलाव के रूप में देखा जा सकता है। जो व्यक्ति पहले मुख्य रूप से नकदी और अनौपचारिक वित्तीय माध्यमों पर निर्भर था, उसके पास अब औपचारिक बैंक खाता उपलब्ध है। खाताधारक सरकारी सहायता सीधे खाते में प्राप्त कर सकता है, सुरक्षित तरीके से बचत कर सकता है, डिजिटल भुगतान कर सकता है, बीमा सुविधा हासिल कर सकता है और पात्रता के आधार पर औपचारिक ऋण तक पहुंच बना सकता है। इससे वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता और नागरिकों की औपचारिक भागीदारी को बढ़ावा मिला है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के व्यापक सुशासन मॉडल में तकनीक, बैंकिंग और कल्याणकारी योजनाओं को आपस में जोड़ने पर जोर रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण नींव बनी है। जन धन खातों को आधार और डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे से जोड़ने से सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक सीधे पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूती मिली है। इस व्यवस्था ने सरकारी सहायता के वितरण को अधिक लक्षित और पारदर्शी बनाने में भी भूमिका निभाई है। इससे लाभार्थी और सरकारी तंत्र के बीच सीधे वित्तीय संपर्क का आधार तैयार हुआ है।

वित्तीय समावेशन की यात्रा हालांकि अभी पूरी नहीं हुई है। अगले चरण में केवल बैंक खातों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि लोग इन खातों और उनसे जुड़ी वित्तीय सेवाओं का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए वित्तीय साक्षरता बढ़ाना, साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा मजबूत करना, सस्ती और आसान ऋण सुविधा उपलब्ध कराना तथा बीमा और पेंशन योजनाओं को लेकर जागरूकता बढ़ाना जरूरी होगा। खासकर ग्रामीण और कम आय वाले परिवारों के लिए वित्तीय सेवाओं को सरल, सुलभ और सुरक्षित बनाना अगली बड़ी प्राथमिकता हो सकती है।

पिछले 12 वर्षों के आंकड़े वित्तीय समावेशन के विस्तार की बड़ी तस्वीर पेश करते हैं। 14.72 करोड़ से बढ़कर 59.09 करोड़ जन धन खाते, 15,670 करोड़ रुपए से बढ़कर 3.16 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जमा राशि और 32.92 करोड़ महिला लाभार्थी इस बदलाव के प्रमुख संकेतक हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 'Banking for All, Empowerment for All' का विजन अब करोड़ों लोगों के लिए ठोस वित्तीय अवसर में बदलता दिखाई देता है।

लोकायन 2026 अभियान के तहत भारतीय नौ–सेना का सुदर्शनी पोत बार्सिलोना पहुंचा

नई दिल्ली, 02 सितम्बर।

भारतीय नौसेना का नौवहन प्रशिक्षण पोत, आईएनएस सुदर्शनी, वैश्विक समुद्री अभियान लोकायन 26 के तहत 01 सितंबर 2026 को स्पेन के दूसरे सबसे बड़े शहर और उत्तरपूर्वी तट पर स्थित बार्सिलोना पहुंचा।

बार्सिलोना में ठहराव के दौरान, यह पोत स्पेन की नौसेना और अन्य समुद्री पक्षकारों के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होगा। आईएनएस सुदर्शनी पर सवार प्रशिक्षु नाविक, पेशेगत संवाद और नौवहन कौशल साझा करने संबंधी कार्यक्रम में भाग लेंगे।

आईएनएस सुदर्शनी 4 सितंबर 2026 को आगंतुकों का स्वागत करेगा। पोत पर पहुंचने वाले लोगों को भारत की समुद्री परंपराओं और उसके महासागरीय अभियानों को जानने का अवसर मिलेगा। लोकायन

26– भारत के विशिष्ट समुद्री प्रयासों का प्रतीक है, जो वैश्विक समुद्री गतिविधियों में भारत की श्रेष्ठता तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण और नौवहन अभियानों में नौसेना की उत्कृष्टता हासिल करने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।

शपथ पत्र

मैं, रमेश, पिता मणि, निवासी डिग्नाबाद गाँव, श्री विजय पुरम तहसील, दक्षिण अण्डमान ज़िला, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, एतद्द्वारा गंभीरतापूर्वक पुष्टि और घोषणा करता हूँ कि :

1. मैं इन द्वीपों का निवासी हूँ और ऊपर बताए गए पते पर रहता हूँ।
2. मेरी माँ का असली और सही नाम रेवती (REVATHI) है, जैसा कि मेरे जन्म प्रमाणपत्र में दर्ज है।
3. मेरे NIOS 10वीं पास प्रमाणपत्र/मार्कशीट (प्रमाणपत्र संख्या A/12 048652) में मेरी माँ का नाम गलत तरीके से 'रेवाफी' (REVAPHY) दर्ज हो गया है, जबकि उनका असली और सही नाम 'रेवती' (REVATHI) है।
4. हालाँकि, ऊपर बताए गए नाम 'रेवाफी' (REVAPHY) और 'रेवती' (REVATHI) एक ही व्यक्ति के नाम हैं।
5. मैं यह शपथ पत्र अपनी माँ का असली और सही नाम घोषित करने के उद्देश्य से दे रहा हूँ; अब से सभी आधिकारिक और गैर–आधिकारिक कार्यों के लिए मेरा नाम 'रमेश, पुत्र रेवती' (RAMESH, S/o. REVATHI) माना जाएगा, इसलिए यह शपथ पत्र दिया जा रहा है।

मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त बयान मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

स्थानः श्री विजय पुरम

दिनांकः 18.08.2026

शपथकर्ता

शपथ पत्र

मैं, के. रम्या, पुत्री एन. कवि, निवासी वल्लुवर नगर, बैम्बूफ्लैट गाँव, दक्षिण अण्डमान ज़िला, एतद्द्वारा गंभीरतापूर्वक पुष्टि और घोषणा करती हूँ कि : –

1. मैं इन द्वीपों की स्थायी निवासी हूँ और ऊपर बताए गए पते पर रहती हूँ।
2. मेरी सीबीएसई मार्कशीट में मेरे पिता का नाम गलती से 'एन कवि' के बजाय 'कवि' दर्ज हो गया है, जबकि मेरे आधार कार्ड नंबर 5120 8446 9473 और अन्य दस्तावेजों में उनका नाम 'एन कवि' है।
3. मेरे पिता का वास्तविक और सही नाम 'एन कवि' है।
4. 'कवि' और 'एन कवि' एक ही व्यक्ति हैं।
5. मैं सक्षम अधिकारी से अपने पिता का नाम ठीक करवाने के लिए यह शपथ पत्र दे रही हूँ, जिसकी सभी कार्यों के लिए आवश्यकता है; इसलिए यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

उपर्युक्त कथन मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

स्थानः श्री विजय पुरम

शपथकर्ता

'कैच द रेन' अभियान में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी

नई दिल्ली, 02 सितंबर (हि.स.)।

बारिश के पानी को सहेजने और भूजल पुनर्भरण के प्रयासों में छत्तीसगढ़ ने देश में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। जलशक्ति मंत्रालय के 'जल संचय जन भागीदारी' और 'कैच द रेन' अभियान में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए तीसरे चरण में देश में पहला स्थान हासिल किया है।

नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित जलशक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के जनभागीदारी आधारित जल संरक्षण मॉडल को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया। सम्मेलन के 'कैच द रेन' सत्र में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्य में वर्षा जल संचयन, भू–जल पुनर्भरण और पेयजल स्रोतों के संरक्षण से जुड़े प्रयासों की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री साय ने देशभर में जल संरक्षण को और प्रभावी बनाने के लिए हर राज्य का अपना 'कैच द रेन' प्लान, बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए 'स्टेट वाटर अवार्ड्स', बिसाग –एन के माध्यम से जल संरचनाओं की मैपिंग और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हर तीन महीने समीक्षा का सुझाव दिया। साय ने कहा कि वे किसान के बेटे हैं और अपने गांव बगिया में स्वयं हल चलाकर खेती कर चुके हैं इसलिए पानी की कीमत को करीब से समझते हैं।

केंद्र सरकार ने चीनी स्टॉक रखने की सीमा घटाकर 2,000 क्विंटल की, जमाखोरी और सट्टेबाजी पर अंकुश

नई दिल्ली, 02 सितम्बर।

केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और जमाखोरी तथा सट्टेबाजी को रोकने के लिए चीनी व्यापारियों के लिए स्टॉक रखने की सीमा 4,000 क्विंटल से घटाकर 2,000 क्विंटल कर दी है। यह निर्णय 15 सितंबर, 2026 से 30 नवंबर, 2026 तक प्रभावी रहेगा।

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। वर्तमान में, देश भर के चीनी व्यापारियों पर 1 अगस्त, 2026 से 4,000 क्विंटल की स्टॉक रखने की सीमा लागू है। सरकार ने अब इस सीमा को घटाकर 2,000 क्विंटल करने का निर्णय लिया है।

संशोधित प्रावधानों के तहत एक चीनी व्यापारी को निम्नलिखित कार्य करने होंगे–

किसी भी स्टॉक को उसकी प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक अपने पास न रखें। देश भर में किसी भी स्थान पर, किसी भी समय, 2,000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार न रखें। हालांकि, क्षेत्र की विशिष्ट बाजार जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, कोलकाता और इसके विस्तारित महानगरीय क्षेत्रों के लिए स्टॉक रखने की सीमा 4,000 क्विंटल ही रहेगी ।

कोलकाता क्षेत्र उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चीनी प्राप्त करता है और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के पूर्वी भाग को इसकी आपूर्ति करता है। इसलिए, कोलकाता और इसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के लिए 4,000 क्विंटल की मौजूदा सीमा को बरकरार रखा गया है।

इस उपाय का उद्देश्य जमाखोरी पर और अंकुश लगाना, सट्टेबाजी को हतोत्साहित करना और चीनी के अत्यधिक भंडार के संचय को रोकना है। इससे आपूर्ति श्रृंखला में चीनी की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित होगी और उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर चीनी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

इतिहास के पन्नों में 03 सितम्बरः जब दुनिया ने देखा पहला आधिकारिक पोलो मैच

नई दिल्ली, 02 सितम्बर (हि.स.)।

दुनिया के सबसे पुराने टीम खेलों में शामिल पोलो का इतिहास दो हजार साल से भी अधिक है। हालांकि आधुनिक पोलो के इतिहास में 03 सितंबर 1875 की तारीख बेहद खास है। इसी दिन अर्जेंटीना में आयोजित अर्जेंटाइन ओपन पोलो टूर्नामेंट के दौरान वह मुकाबला खेला गया, जिसे दुनिया का पहला आधिकारिक पोलो मैच माना जाता है।

पोलो की शुरुआत को लेकर भारत का इतिहास भी बेहद समृद्ध है। आधुनिक पोलो को भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय अक्सर मुगलों को दिया जाता है। हालांकि ब्रिटिशों के भारत आने से काफी पहले ही मणिपुर में 'सागो कांगजेई' नामक पारंपरिक खेल खेला जाता था, जिसे आधुनिक पोलो का शुरुआती रूप माना जाता है। यही वजह है कि मणिपुर को पोलो का जन्मस्थान भी कहा जाता है।

ब्रिटिश शासन के दौरान पोलो को नया स्वरूप मिला और यह भारतीय रियासतों के बीच भी तेजी से लोकप्रिय हुआ। ब्रिटिश कप्तान रॉबर्ट स्टीवर्ट ने भारत में इस खेल को व्यवस्थित रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश अधिकारियों ने असम के सिलचर में पोलो क्लब की स्थापना की, जिसके बाद यह खेल देश के अन्य हिस्सों में भी फैलता गया। 1892 में इंडियन पोलो एसोसिएशन की स्थापना भारत में इस खेल के संगठित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। उस दौर में जयपुर, भोपाल, अलवर, बीकानेर और हैदराबाद जैसी रियासतों की अपनी मजबूत पोलो टीमें हुआ करती थीं।

आजादी के बाद भी भारत में पोलो की लोकप्रियता बनी रही। भारतीय पोलो ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। 1957 में भारतीय पोलो टीम ने फ्रांस में आयोजित विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतकर देश का गौरव बढ़ाया।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र–1650 – इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड के बीच डनबर की लड़ाई।

1783– अमेरिका और ब्रिटेन के बीच पेरिस की संधि के साथ क्रांतिकारी युद्ध समाप्त हो गया।

1833– अमेरिका में पहला सफल समाचार पत्र 'न्यूयार्क सन' बेंजामिन एच डे के द्वारा शुरू किया गया था।

1900– रूसी सेना ने रूस तथा मंचूरियाई सीमा के दोनों तरफ आमूर नदी पर नियंत्रण स्थापित किया।

1918– प्राचीन इस्लामी नगर दमिश्क पर ब्रिटेन की सेना का अधिकार हो गया।

1924– चीन में गृह युद्ध की शुरुआत।

1939– ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविले चेम्बरलिन द्वारा एक रेडियो प्रसारण पर ब्रिटेन और फ्रांस का जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ।

1943– दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने इटली पर हमला किया।

1950– एमीलियो नीनो फरिना पहले फॉर्मूला–1 वर्ल्ड चैपियन बने।

1984– दक्षिण फिलिपीन्स में आये एक भयानक तूफान की वजह से करीब 1300 मारे गए और सैकड़ों घायल हुए।

अमेठी में बनी 100 प्रतिशत स्वदेशी एके–203 'शेर' असॉल्ट राइफल का सफल ट्रायल

नई दिल्ली, 02 सितम्बर।
उत्तर प्रदेश के अमेठी में तैयार हुई देश की पहली पूरी तरह स्वदेशी एके–203 राइफल 'शेर' भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने जा रही है। अमेठी के कोरवा स्थित संयंत्र में बनी इस राइफल की खास बात यह है कि इसमें इस्तेमाल किया गया हर पुर्जा और कच्चा माल भारतीय उद्योग से लिया गया है।

एके–203 राइफल को भारतीय सेना की दशकों पुरानी 5.56 मिलीमीटर INSAS राइफल की जगह शामिल किया जा रहा है। भारत–रूस सहयोग से शुरू हुई यह परियोजना अब पूरी तरह स्वदेशी उत्पादन के स्तर तक पहुंच गई है। डिजाइन रूसी मूल का जरूर है, लेकिन 'शेर' नाम से तैयार इस संस्करण का उत्पादन भारतीय उद्योग की पूरी श्रृंखला पर आधारित है।

रक्षा मंत्रालय और इंडो–रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच करीब 6.01 लाख एके–203 राइफलों की आपूर्ति का करार हुआ है। इस अनुबंध की कीमत करीब 5,200 करोड़ रुपये बताई गई है। पूरी तरह स्वदेशी संस्करण का परीक्षण भारतीय सेना सितंबर में करेगी।

शुरुआती दौर में कोरवा संयंत्र में रूस से मिली तकनीक के आधार पर राइफलों का निर्माण शुरू हुआ था। उस समय राइफल में विदेशी उपकरणों और पुर्जों का इस्तेमाल होता था। अब इ से पूरी तरह भारतीय पुर्जों और कच्चे माल से तैयार किया गया है। राइफल का फायरिंग और बर्स्ट फायरिंग परीक्षण भी किया जा चुका है।

कंपनी को कुल 6,01,427 राइफलों की आपूर्ति अक्टूबर 2032 तक करनी है। हालांकि उत्पादन क्षमता बढ़ाकर इस लक्ष्य को तय समय से पहले, दिसंबर 2030 तक पूरा करने की योजना है। वर्ष 2026 से उत्पादन क्षमता बढ़ाकर करीब 12 हजार राइफल प्रतिमाह करने का लक्ष्य रखा गया है। कोरवा संयंत्र में उत्पादन व्यवस्था को इस स्तर तक विकसित करने की योजना है कि भविष्य में हर 100 सेकंड में एक एके–203 राइफल तैयार की जा सके।

7.62×39 मिलीमीटर क्षमता वाली एके–203 को मजबूत, विश्वसनीय और संचालन में आसान आधुनिक असॉल्ट राइफल माना जा रहा है। इसे उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के साथ–साथ आतंकवाद रोधी अभियानों में तैनात जवानों के प्रमुख व्यक्तिगत हथियार के रूप में शामिल करने की तैयारी है। अमेठी के कोरवा संयंत्र में बनी यह पूरी तरह स्वदेशी 'शेर' राइफल भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए भारतीय भाषाओं का उपयोग महत्वपूर्णः केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

नई दिल्ली, 02 सितम्बर।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे. पी. नड्डा ने मंगलवार को स्वास्थ्य क्षेत्र में हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के अधिक से अधिक उपयोग का आह्वान करते हुए कहा कि लोगों से उनकी भाषा में संवाद करने से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और उन्हें आम जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है।

दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय की 'हिंदी सलाहकार समिति' की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने कहा कि देश पश्चिमी दुनिया के औपनिवेशिक प्रभाव से निकलकर भारतीय भाषाओं के अधिक उपयोग की ओर बढ़ रहा है और भाषा "भारतीयता" को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण अवसरों पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिंदी में अपने विचार और दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं तथा भारतीयता को मजबूत करने पर बल दिया है।" बैठक में मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा के रूप में हिंदी के उपयोग की समीक्षा की गई, साथ ही इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अब तक उठाए गए कदमों और भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा की गई।

उन्होंने ने मंत्रालय के तहत 'राजभाषा' के पदों की समीक्षा करने और समयबद्ध तरीके से रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से ऐसे रिक्त पदों की सूची तैयार कर जल्द से जल्द सौंपने

को कहा, ताकि इस मामले को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया जा सके। अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने पूरे सप्ताह की गतिविधियों के स्पष्ट कार्यक्रम के साथ एक सप्ताह का संक्षिप्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या कार्यशाला आयोजित करने का सुझाव दिया।

उन्होंने सुझाव दिया कि मंत्रालय की पत्रिकाओं में प्रकाशित कम से कम आधे लेख हिंदी में होने चाहिए और बुलेटिनों में भी हिंदी का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए। भोपाल मेडिकल कॉलेज में हिंदी में मेडिकल शिक्षा प्रदान करने के उपयोग का उल्लेख करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि इस पहल का अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि यह समझा जा सके कि इसे अन्य संस्थानों में कैसे दोहराया जा सकता है। समिति की पिछली बैठक 22 अगस्त 2025 को नयी दिल्ली में आयोजित की गई थी।

भारत में ब्रिक्स सम्मेलन का मंचः दिल्ली में जुटेंगे दुनियाभर के दिग्गज, यूएन महासचिव गुटेरेस भी लेंगे हिस्सा

संयुक्त राष्ट्र, 02 सितम्बर।
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस महीने के आखिर में नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस साल अध्यक्ष होने के नाते, भारत 12–13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के नेताओं के साथ–साथ विशेष रूप से आमंत्रित अतिथि भी शामिल होंगे। गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने मंगलवार को कहा कि हमें अभी आधिकारिक तौर पर यह घोषणा करनी है कि महासचिव लगभग 10 दिनों में नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स बैठक में भाग लेंगे।

बता दें कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय 'लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण' है। भारत के 25 से अधिक शहरों में 350 से अधिक बैठकें और उच्च–स्तरीय बातचीत हुई हैं, ताकि ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी को तीन मुख्य आधारों पर मजबूत किया जा सके। इनमें राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय तथा सांस्कृतिक और लोगों के बीच आदान–प्रदान शामिल हैं।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन कार्यक्रमों और बिजनेस–टू–बिजनेस तथा लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने वाली पहलों के माध्यम से, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ने व्यावहारिक और विकास–उन्मुख परिणामों के जरिए ब्रिक्स सहयोग को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है।

69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत रखेगा एआई, जलवायु लचीलापन और मानवाधिकारों पर पक्ष

नई दिल्ली, 02 सितंबर (हि.स.)।
भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल 13 से 19 सितंबर तक दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित होने वाले 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन (सीपीसी) में हिस्सा लेगा। सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), जलवायु लचीलापन, समावेशी व्यापार, मानवाधिकार और संसदीय लोकतंत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण रखेगा।

सम्मेलन की तैयारियों को लेकर कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय ब्रीफिंग बैठक हुई। बैठक में बिरला ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल की प्रभावी भागीदारी पर जोर देते हुए सभी सदस्यों और महिला प्रतिनिधियों से निर्धारित सत्रों तथा कार्यशालाओं में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने का आह्वान किया।

उन्होंने प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान भारत के राष्ट्रीय हितों और दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का आग्रह किया। साथ ही सम्मेलन के बैठकों में समयबद्धता और अनुशासन का विशेष ध्यान रखने को कहा, ताकि भारतीय प्रतिनिधिमंडल एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर सके।

इस वर्ष सम्मेलन की मुख्य थीम "बदलती वैश्विक व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय कानून और संसदीय लोकतंत्र को सशक्त बनाना : राष्ट्रमंडल की नेतृत्वकारी भूमिका" है। इसके तहत बदलती वैश्विक व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय कानून और संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में संसदों की भूमिका पर चर्चा होगी।

ब्रीफिंग के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए छह प्रमुख सीपीसी कार्यशालाओं के एजेंडे पर भी चर्चा हुई।

इनमें विविध अर्थव्यवस्थाओं में समावेशी और निष्पक्ष व्यापार, सुलभ संसद और दिव्यांगजनों का समावेशन, जलवायु अनुकूलन एवं लचीलापन, संसदों में एआई के वर्तमान अनुप्रयोग, मानवाधिकारों की रक्षा तथा पश्च–विधायी संवीक्षा जैसे विषय शामिल हैं।

सम्मेलन में लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी और उनके विश्वास को मजबूत करने पर भी विशेष चर्चा होगी। इसके तहत "लोकतंत्र में युवाओं के विश्वास और भागीदारी को मजबूत करना" विषय पर युवा गोलमेज बैठक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा सीपीए महासभा की डिबेट भी होगी।

महिला सांसदों से जुड़े मुद्दों पर 10वें राष्ट्रमंडल महिला संसद सदस्य (सीडब्ल्यूपी) सम्मेलन के तहत "लैंगिक संवेदनशीलता को संस्थागत दायित्व बनाना" विषय पर चार विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें लैंगिक संवेदनशीलता को संस्थागत जिम्मेदारी बनाने पर विचार–विमर्श होगा।

राष्ट्रीय पोषण सप्ताहः निरोगी रहने के लिए संतुलित आहार जरूरी, जानिए कैसी होनी चाहिए आपकी थाली

नई दिल्ली, 02 सितम्बर।
अच्छी सेहत की शुरुआत हमारी थाली से होती है। हम रोज क्या खाते हैं, कितनी मात्रा में खाते हैं और हमारे भोजन में पोषक तत्वों का कितना संतुलन है। इसका सीधा असर शरीर की ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, विकास और लंबे समय तक स्वस्थ रहने पर पड़ता है। यही वजह है कि हर साल 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इस दौरान लोगों को संतुलित आहार, पोषण और स्वस्थ खानपान की आदतों के प्रति जागरूक किया जाता है।

भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत 1982 में की गई थी। इसका मकसद लोगों को यह समझाना था कि खाना केवल पेट भरने का नाम नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, फाइबर और पर्याप्त पानी का सही संतुलन होना जरूरी है। अक्सर हम मान लेते हैं कि घर का बना खाना अपने आप संतुलित और पौष्टिक होता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर किसी भोजन में रोटी या चावल की मात्रा ज्यादा है और दाल, सब्जी, दही या अन्य प्रोटीन स्रोत बहुत कम हैं, तो पेट तो भर सकता है, लेकिन शरीर की सभी पोषण संबंधी जरूरतें पूरी नहीं होतीं। इसीलिए संतुलित थाली में अलग–अलग खाद्य को शामिल करना जरूरी है।

अनाज के साथ दाल या कोई अन्य प्रोटीन स्रोत, हरी सब्जियां, मौसमी फल और दूध या दही जैसे खाद्य पदार्थ भोजन को ज्यादा पौष्टिक बना सकते हैं।हालांकि एक अच्छी और संतुलित थाली के लिए बहुत महंगी चीजों की जरूरत नहीं है। हमारे घरों में आसानी से मिलने वाले खाद्य पदार्थों से ही पौष्टिक भोजन तैयार किया जा सकता है। अनाजः रोटी, चावल, दलिया, पोहा, उपमा, ओट्स या बाजरा, ज्वार और रागी जैसे मोटे अनाज भोजन का हिस्सा हो सकते हैं।

प्रोटीनः दाल, राजमा, चना, छोले, सोयाबीन, पनीर, दूध, दही, अंडा, मछली या अन्य उपलब्ध प्रोटीन स्रोत शरीर के लिए जरूरी हैं। खासकर बच्चों, किशोरों और बढ़ती उम्र के

लोगों के लिए पर्याप्त प्रोटीन महत्वपूर्ण है।
सब्जियांः भोजन में हरी पत्तेदार और दूसरी रंग–बिरंगी सब्जियों को शामिल करना चाहिए। अलग–अलग रंग की सब्जियां कई तरह के विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्व उपलब्ध कराती हैं
फलः मौसमी फल रोज की डाइट का हिस्सा बनाए जा सकते हैं। फल खाने को प्राथमिकता दें और मीठे पेय या ज्यादा चीनी वाले जूस की जगह पूरा फल लेना बेहतर विकल्प हो सकता है।
दूध और दुग्ध उत्पादः दूध, दही और अन्य डेयरी उत्पाद कैल्शियम और प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों के स्रोत हो सकते हैं। वहीं, आज की व्यस्त जिंदगी में चिप्स, बिस्किट, इंस्टेंट नूडल्स, मिठाइयां, मीठे पेय और दूसरे पैकेज्ड स्नैक्स आसानी से हमारी डाइट का हिस्सा बन जाते हैं। कभी–कभार इनका सेवन अलग बात है, लेकिन इन्हें रोजमर्रा के भोजन का विकल्प बना लेना ठीक नहीं है।

खासकर बच्चों और युवाओं में स्क्रीन टाइम के साथ स्नैकिंग की आदत बढ़ रही है। टीवी या मोबाइल देखते हुए बिना ध्यान दिए ज्यादा खाना भी हमारी कुल कैलोरी बढ़ा सकता है। इसलिए खाने के समय भोजन पर ध्यान देना और पैकेट से सीधे खाने के बजाय उचित मात्रा निकालकर खाने की आदत डालें।

वायुसेना में गैर–चिकित्सा शाखा से एयर वाइस मार्शल बनने वाली पहली महिला अधिकारी बनी शक्ति शर्मा

नई दिल्ली, 02 सितम्बर।
भारतीय वायुसेना में एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा ने इतिहास रच दिया है। वह गैर–चिकित्सा शाखा से इस पद तक पहुंचने वाली भारतीय सशस्त्र सेनाओं की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। उनकी यह उपलब्धि सेना में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, शक्ति शर्मा को वायुसेना मुख्यालय में सहायक वायुसेना प्रमुख (शिक्षा) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। करीब तीन दशक से अधिक लंबे अपने सेवाकाल में उन्होंने प्रशिक्षण संस्थानों, फील्ड स्टेशनों, कमान मुख्यालय और वायुसेना मुख्यालय में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं।

शक्ति शर्मा को 1994 में भारतीय वायुसेना की शिक्षा शाखा में नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्होंने अलग–अलग पदों पर काम करते हुए शिक्षा और प्रशिक्षण से जुड़े क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह चिकित्सा शाखा से बाहर वायुसेना में ग्रुप कैप्टन का पद हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी भी रही हैं। उनके करियर में कई ऐसी उपलब्धियां हैं, जिन्होंने सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं के लिए नए रास्ते खोले हैं।

एयर वाइस मार्शल बनने से पहले शक्ति शर्मा ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी। वह तीनों सेनाओं में पहली महिला अधिकारी बनी थीं, जिन्होंने सैनिक स्कूल की कमान संभाली। उन्होंने कपूरथला स्थित सैनिक स्कूल की

प्रधानाचार्य के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई। इस दौरान शिक्षा और संस्थागत विकास से जुड़े कामों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

शक्ति शर्मा ने भारतीय वायुसेना और प्रमुख शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग मजबूत करने में भी योगदान दिया। उन्होंने आईआईटी कानपुर और पुणे विश्वविद्यालय में वायुसेना की 'चेयर ऑफ एक्सीलेंस' स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन पहलों का उद्देश्य वायुसेना और उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच शोध, शिक्षा और विशेषज्ञता के आदान–प्रदान को बढ़ावा देना है। रक्षा मंत्रालय ने शक्ति शर्मा की पदोन्नति को भारतीय रक्षा बलों में महिला अधिकारियों की यात्रा का नया अध्याय बताया। मंत्रालय ने कहा कि तीन दशक से अधिक की शानदार सेवा के बाद उनकी यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है।

एशियन गेम्स में भवानी देवी करेंगी 20 सदस्यीय तलवारबाजी दल की अगुवाई

नई दिल्ली, 02 सितम्बर।
ओलंपियन ८। भवानी देवी दो महीने के अंतराल के बाद प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में वापसी करते हुए आगामी एशियाई खेलों के लिए चुनी गई 20 सदस्यीय भारतीय तलवारबाजी टीम की अगुवाई करेंगी। भवानी देवी इस साल आयोजित एशियाई सीनियर तलवारबाजी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के बाद आइची–नागोया एशियाई खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगी।

चयनित सभी खिलाड़ी मंगलवार से 15 सितंबर तक पटियाला के राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनआईएस) में राष्ट्रीय तैयारी शिविर में हिस्सा लेंगे। इसके बाद टीम 16 सितंबर को सीधे आइची–नागोया रवाना होगी जहां प्रतियोगिता से पहले परिस्थितियों से अभ्यस्त होने की तैयारी की जाएगी।

भारतीय तलवारबाजी संघ (एफएआई) की चयन समिति ने राष्ट्रीय रैंकिंग और इस साल प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर टीम का चयन किया। इनमें एशियाई सीनियर तलवारबाजी चैंपियनशिप, विश्व तलवारबाजी चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप शामिल हैं।

टीम में तीनों वर्गों फॉयल, एपी और साबरे में मजबूत खिलाड़ी शामिल हैं। एपी वर्ग में महिलाओं की टीम में

तनिष्का खत्री और प्राची लोहान प्रमुख दावेदार होंगी। दोनों ने राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीतकर प्रभावित किया था।

राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में पुरुष साबरे में स्वर्ण पदक जीतने वाले करण सिंह गुर्जर के प्रदर्शन से इस वर्ग में भारत की पदक की उम्मीदें मजबूत हुई हैं। वहीं तेजस मनोज पाटिल ने पुरुष फॉयल में अपना स्थान पक्का किया है। उन्होंने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था और इस प्रतियोगिता के सीनियर फॉयल वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय तलवारबाज बने थे।

आईसीसी का बड़ा ऐलान, भारत को मिली पहली वूमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी

आईसीसी वूमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आईसीसी ने पहली बार आयोजित होने वाली वूमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी 2027 की मेजबानी भारत को सौंप दी है। इसके साथ ही टूर्नामेंट की तारीखों और वेन्यू का ऐलान भी कर दिया गया है। 6 टीमों वाला यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट अगले साल 14 से 28 फरवरी तक भारत में खेला जाएगा। आईसीसी के अनुसार, टूर्नामेंट के सभी मुकाबले मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया और वडोदरा के वडोदरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होंगे। इस टूर्नामेंट में भारत समेत दुनिया की 6 दिग्गज टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी।

आईसीसी वूमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी 2027 का आयोजन पहले श्रीलंका में होना था, लेकिन आईसीसी की वार्षिक बैठक में तय सुधारों को लागू करने की प्रक्रिया जारी रहने के कारण टूर्नामेंट को भारत स्थानांतरित कर दिया गया। नए मेजबान के चयन के लिए आईसीसी ने बांग्लादेश, भारत और साउथ अफ्रीका के नामों पर विचार किया। इसके बाद भारत को मेजबानी के लिए चुना गया और 1 सितंबर को आईसीसी बोर्ड ने इस फैसले को मंजूरी दे दी।

आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने इसे महिला क्रिकेट के लिए एक रोमांचक नए दौर की शुरुआत बताया। टूर्नामेंट के पहले संस्करण के तौर पर यह दुनिया की बेहतरीन टीमों को एक जबरदस्त और हाई लेवल मुकाबले के लिए एक साथ लाएगा। इस टूर्नामेंट में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका हिस्सा लेंगी। सभी मुकाबले ट20 प्रारूप में खेले जाएंगे। 6 टीमें राउंड–रोबिन फॉर्मेट में एक–दूसरे से भिड़ेंगी, जिसके बाद शीर्ष दो टीमें 28 फरवरी को होने वाले फाइनल में जगह बनाएंगी। भारत महिला आईसीसी वर्ल्ड कप चैंपियन है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में इंग्लैंड में खेले गए महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। ऐसे में पहली वूमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।